Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide adequate warehouse facilities for foodgrains in Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में पूर्व में हुए बड़े खाद्यान्न घोटाले जिसकी सी.बी.आई. जांच लंबे समय से हो रही है, की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें उक्त खाद्यान्न व्यापारी जो आरोपी है, में से कई ने अपने प्राइवेट गोदाम सरकारी क्रय व वितरण एजेंसियों को उपलब्ध करा रखे थे, जिसकी आड़ में व कागजों में हेरा-फेरी करके गरीबों को सरकारी सब्सिडी पर दिया जाने वाला गेहूँ व चावल आदि काला बाज़ारी करने के अलावा विदेशों तक भेज दिया गया था। भण्डार की कम सरकारी क्षमता जहां एक ओर भ्रऐटाचार को बढ़ावा देती है, वही चोरी, खाद्यान्न की बर्बादी, बढ़ी कीमतों व कागजी खरीद वितरण द्वारा हेरा-फेरी का अवसर भी देती है।

मैं सरकार का ध्यान सरकारी क्रय केंद्रों द्वारा खरीदे गये अनाज व पी.डी.एस. आदि खाद्यान्न योजनाओं हेतु आवश्यक भण्डार क्षमता की कमी विशेऐाकर उत्तर प्रदेश की ओर जहां गोदामों की कमी के कारण सरकारी अनाज (खरीद व वितरण) के लिए प्राइवेट गोदाम किराये पर लिये जाते हैं, की ओर दिलाना चाहता हूँ। आश्चर्यजनक है कि वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम स्वयं के गोदामों से अधिक भण्डार क्षमता प्राइवेट (खाद्यान्न व्यवसायियों के) गोदामों की है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि खाद्यान्न माफियाओं पर शिकंजा कसने व नुकसान से बचने के लिए सरकार भण्डारण हेतु आवश्यकताओं के अनुसार गोदामों का निर्माण कराये।